

Weekly One Liners 30th December to 5th January 2025

आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, 2024

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने दिसंबर 2024 के लिए अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report - FSR) जारी की है, जो भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिति का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है। यह रिपोर्ट वर्ष में दो बार, आमतौर पर जून और दिसंबर में प्रकाशित होती है, और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता और लचीलापन पर महत्वपूर्ण जानकारी देती है।

दिसंबर 2024 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की मुख्य बातें:

1. बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता (Asset Quality):

सितंबर 2024 तक भारतीय बैंकों का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Gross NPAs) का अनुपात घटकर 12 वर्षों के निचले स्तर 2.6% पर आ गया है। यह सुधार बुरी ऋणों की वसूली, पुराने ऋणों के राइट-ऑफ और खराब परिसंपत्तियों की वृद्धि में कमी के कारण हुआ है।

2. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का अनुमान (NPA Projections):

रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2026 तक सकल खराब ऋण अनुपात आधारभूत स्थिति (Baseline Scenario) में बढ़कर 3% तक हो सकता है, और उच्च-जोखिम स्थितियों (High-Risk Scenarios) में यह 5.3% तक पहुंच सकता है। हालांकि, RBI ने आश्वासन दिया है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कोई भी बैंक न्यूनतम पूंजी आवश्यकता (9%) से नीचे नहीं जाएगा।

3. आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान (Economic Growth Forecast):

RBI ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 6.6% GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, जो कि वर्ष के पहले छमाही की सुस्ती के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

4. तरलता घाटा (Liquidity Deficit):

बैंकिंग प्रणाली में तरलता की भारी कमी है, जो आगामी तिमाही में और बढ़ने की संभावना है। 23 दिसंबर 2024 तक तरलता घाटा 2.43 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया था, जो कर-आउटफ्लो और विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप जैसे कारकों से प्रेरित है। बाजार विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि इस समस्या को हल करने के लिए खुले बाजार में बॉन्ड की खरीद या नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में कटौती जैसे उपाय किए जा सकते हैं।

5. नियामकीय अनुपालन (Regulatory Compliance):

जून से नवंबर 2024 की अवधि में RBI द्वारा लगाए गए मौद्रिक दंड में 47% की कमी आई है, जो लगभग 30 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 57 करोड़ रुपये से अधिक थी। यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों में बेहतर नियामकीय अनुपालन को दर्शाता है।

6. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs):

NBFCs की बैलेंस शीट मजबूत हुई है, और तनाव परीक्षणों (Stress Tests) से संकेत मिलता है कि उच्च जोखिम वाली स्थितियों में भी उनकी पूंजी आवश्यकताएं न्यूनतम स्तर से काफी ऊपर बनी रहेंगी।

RBI की भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2023-24

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने "भारत में बैंकिंग का प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट 2023-24" जारी की है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। यह वार्षिक रिपोर्ट बैंकिंग उद्योग के विभिन्न पहलुओं जैसे परिसंपत्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता, पूंजी पर्याप्तता और उभरती चुनौतियों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है।

भारत में बैंकिंग का प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट 2023-24 की मुख्य बातें:

1. बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता (Asset Quality):

सितंबर 2024 तक भारतीय बैंकों का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (GNPA) का अनुपात घटकर 2.5% हो गया है, जो 2012 के बाद का सबसे निचला स्तर है। यह सुधार वसूली, पुराने बकाया ऋणों के राइट-ऑफ और परिसंपत्ति गुणवत्ता के बेहतर प्रबंधन का परिणाम है। खराब ऋणों में यह कमी जोखिम प्रबंधन और वसूली प्रयासों की प्रभावशीलता को दर्शाती है।

2. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का अनुमान (NPA Projections):

रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2026 तक सकल खराब ऋण अनुपात आधारभूत स्थिति में बढ़कर 3% तक हो सकता है। उच्च जोखिम स्थितियों में, यह 5.3% तक पहुंच सकता है। हालांकि, RBI ने आश्वासन दिया है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी होगी और वे 9% न्यूनतम पूंजी आवश्यकता से नीचे नहीं जाएंगे।

3. ऋण वृद्धि और आर्थिक दृष्टिकोण (Credit Growth and Economic Outlook):

2023-24 के दौरान भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने 19% की ऋण वृद्धि दर्ज की, जो सकारात्मक आर्थिक विकास और ऋण की मजबूत मांग को दर्शाती है। बुनियादी ढांचा, आवास और व्यक्तिगत ऋण जैसे क्षेत्रों में अग्रिमों की वृद्धि विशेष रूप से मजबूत रही। यह प्रवृत्ति भारत में आर्थिक माहौल के सुधार का संकेत देती है।

4. बैंकिंग में डिजिटल परिवर्तन (Digital Transformation):

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र डिजिटल क्रांति का अनुभव कर रहा है, जिसमें ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग लेनदेन में वृद्धि हो रही है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) पायलटों की शुरुआत से डिजिटल वित्तीय समाधानों को अपनाने की दिशा में कदम और तेज़ हुए हैं। डिजिटल बैंकिंग की तेज़ी से बढ़ती प्रवृत्ति वित्तीय समावेशन बढ़ाने और ग्राहकों के अनुभव को सुधारने में मदद कर रही है।

BANK MAHAPACK
for all Bank & Insurance Exams
Selection Ka Saathi

5. मजबूत पूंजी पर्याप्तता (Capital Adequacy):

सितंबर 2024 तक भारतीय बैंकों का पूंजी-से-जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (CRAR) 16.8% था, जो 9% की नियामकीय न्यूनतम आवश्यकता से काफी अधिक है। यह संकेत देता है कि भारतीय बैंक किसी भी वित्तीय झटके को सहने के लिए मजबूत स्थिति में हैं।

6. बढ़ते बैंक धोखाधड़ी के मामले (Increasing Bank Frauds):

रिपोर्ट में बैंक धोखाधड़ी के मामलों में चिंताजनक वृद्धि का उल्लेख किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में साइबर सुरक्षा और आंतरिक नियंत्रण को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। RBI इन जोखिमों को कम करने के लिए नए उपायों पर विचार कर सकता है।

प्रत्येक बिंदु का विस्तृत विश्लेषण:

1. परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार:

बैंकिंग क्षेत्र ने परिसंपत्ति गुणवत्ता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। सितंबर 2024 में GNPA अनुपात का 2.5% तक गिरना प्रभावी वसूली प्रयासों और विवेकपूर्ण ऋण देने की प्रथाओं को दर्शाता है। नेट NPA अनुपात का 0.57% तक कम होना परिसंपत्ति गुणवत्ता और बेहतर जोखिम प्रबंधन को रेखांकित करता है।

2. लाभप्रदता में वृद्धि:

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) ने 2023-24 में 1.4% की रिटर्न ऑन एसेट्स (RoA) और 14.6% की रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE) के साथ लगातार लाभप्रदता प्रदर्शित की है। यह वृद्धि बैंकिंग क्षेत्र की लचीलापन और संचालन दक्षता को दर्शाती है।

3. पूंजी पर्याप्तता:

सितंबर 2024 तक 16.8% का CRAR नियामकीय न्यूनतम आवश्यकता को पार करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बैंकों के पास संभावित नुकसान को सहने और विकास का समर्थन करने के लिए पर्याप्त पूंजी है।

4. ऋण वृद्धि:

19% की अग्रिम वृद्धि ऋण की मजबूत मांग और आर्थिक सुधार व विस्तार में विश्वास को दर्शाती है।

5. डिजिटल परिवर्तन:

डिजिटल बैंकिंग लेनदेन में वृद्धि और CBDC पायलटों की शुरुआत से यह स्पष्ट है कि बैंकिंग क्षेत्र आधुनिकरण और वित्तीय समावेशन के प्रति प्रतिबद्ध है।

6. उभरते जोखिम:

मार्च 2026 तक GNPA अनुपात में 3% की वृद्धि और बैंक धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों से बेहतर जोखिम प्रबंधन और सतर्कता की आवश्यकता स्पष्ट होती है।

इसरो ने अंतरिक्ष डॉकिंग के लिए ऐतिहासिक स्पैडेक्स मिशन लॉन्च किया

भारत की अंतरिक्ष यात्रा में बड़ी प्रगति हुई है, क्योंकि इसरो ने सफलतापूर्वक SpaDeX मिशन लॉन्च किया, जो अंतरिक्ष डॉकिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। 30 दिसंबर, 2024 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC SHAR) से PSLV-C60 रॉकेट द्वारा यह मिशन लॉन्च किया गया। इसने दो छोटे अंतरिक्ष यान, SDX01 (चेज़र) और SDX02 (टारगेट), को निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया। इस मिशन ने स्वायत्त डॉकिंग और अनडॉकिंग प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करते हुए इसरो को रूस, अमेरिका और चीन के बाद इस क्षेत्र में चौथा वैश्विक खिलाड़ी बना दिया।

मिशन का उद्देश्य और प्रौद्योगिकी

SpaDeX मिशन का मुख्य उद्देश्य निम्न पृथ्वी कक्षा में अंतरिक्ष यान के मिलन, डॉकिंग और अनडॉकिंग की तकनीक को विकसित करना है। इसमें शामिल हैं:

- **स्वायत्त डॉकिंग:** अंतरिक्ष यान को स्वायत्त रूप से डॉक और अनडॉक करने की महत्वपूर्ण क्षमता का प्रदर्शन।
- **शक्ति स्थानांतरण:** डॉक किए गए अंतरिक्ष यानों के बीच ऊर्जा स्थानांतरण को स्थापित करना, जो भविष्य के अनुप्रयोगों जैसे रोबोटिक्स के लिए आवश्यक है।
- **स्थिति और नेविगेशन:** सटीक नियंत्रण और समन्वय के लिए डिफरेंशियल GNSS-आधारित सैटेलाइट पोजिशनिंग सिस्टम का उपयोग।

स्वदेशी प्रौद्योगिकियां और प्रगति

इस मिशन में कई स्वदेशी तकनीकों को प्रदर्शित किया गया, जिनमें शामिल हैं:

- **डॉकिंग तंत्र:** उच्च सटीकता के लिए डिज़ाइन किया गया एक उन्नत डॉकिंग सिस्टम, जो छोटे अंतरिक्ष यानों के लिए महत्वपूर्ण है।
- **संचार प्रणाली:** कक्षा में पैतरेबाज़ी के दौरान वास्तविक समय संचार के लिए इंटर-सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक (ISL)।
- **सापेक्ष कक्षा निर्धारण:** GNSS-आधारित सापेक्ष कक्षा निर्धारण और प्रसार (RODP) डॉकिंग के दौरान सटीक स्थिति सुनिश्चित करता है।

भारत के अंतरिक्ष भविष्य के लिए महत्व

SpaDeX मिशन की सफलता भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को न केवल बढ़ावा देती है, बल्कि उपग्रह सेवा, अंतरिक्ष स्टेशन असेंबली और चंद्र अन्वेषण जैसे जटिल भविष्य के मिशनों के लिए आधार भी तैयार करती है। यह इसरो की वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में स्थिति को मजबूत करता है और उन्नत अंतरिक्ष मिशनों जैसे चंद्रयान-4, जो पृथ्वी-आधारित GNSS समर्थन के बिना संचालित होगा, के लिए नींव प्रदान करता है। इस मिशन के साथ, भारत गहन अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी नेतृत्व की अपनी दृष्टि के करीब पहुंच रहा है।

116वीं मन की बात

जैसे ही 2025 नज़दीक आ रहा है, भारत अनेक ऐतिहासिक उत्सवों और उपलब्धियों की दहलीज़ पर खड़ा है। यह वर्ष भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जो राष्ट्र के संस्थापकों की दृष्टि और समर्पण का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपनी मासिक रेडियो कार्यक्रम "मन की बात" के 116वें एपिसोड में देश की प्रगति और एकता को लेकर अपनी दृष्टि साझा की, जिसमें सांस्कृतिक धरोहर, स्वास्थ्य, और खेल से जुड़े विभिन्न विषय शामिल थे।

भारतीय संविधान के 75 वर्ष का उत्सव

26 जनवरी 2025 एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि यह भारतीय संविधान के 75 वर्षों की पूर्णता को चिह्नित करता है। यह मार्गदर्शक दस्तावेज़ भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में अडिग खड़ा है।

विशेष वेबसाइट:

- एक विशेष वेबसाइट **constitution75.com** लॉन्च की गई है।
 - नागरिक संविधान की प्रस्तावना पढ़ सकते हैं और अपनी व्याख्या वाले वीडियो अपलोड कर सकते हैं।
 - यह संविधान कई भाषाओं में उपलब्ध है और शिक्षण के लिए एक इंटरएक्टिव मंच प्रदान करता है।

- प्रधानमंत्री ने छात्रों और युवाओं को इस डिजिटल पहल में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, जिससे संविधान की विरासत के साथ गहरा जुड़ाव हो सके।

महाकुंभ 2025: एकता का भव्य उत्सव

13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है।

- **विविधता और एकता:**
 - लाखों भक्त, संत और श्रद्धालु इकट्ठा होकर "एकता के महाकुंभ" के मंत्र को प्रदर्शित करेंगे।
 - बिना किसी भेदभाव के परंपराओं और संप्रदायों का संगम "एक हो पूरा देश" का संदेश देगा।
- **डिजिटल महाकुंभ:**
 - AI-चालित नेविगेशन भक्तों को घाट, मंदिर और अखाड़ों तक पहुंचने में मार्गदर्शन करेगा।
 - AI चैटबॉट, लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर और रियल-टाइम अपडेट जैसी सुविधाएं अनुभव को बेहतर बनाएंगी।
 - प्रधानमंत्री ने प्रतिभागियों को #EktaKaMahakumbh के साथ सेल्फी साझा करने के लिए प्रेरित किया।

कृष, त्रिष और बाल्टीबाँय: ऐतिहासिक नायकों को पुनर्जीवित करना लोकप्रिय एनीमेशन श्रृंखला **KTB - भारत हैं हम** ने स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों को समर्पित अपने दूसरे सीजन की शुरुआत की।

- **विस्तृत पहुंच:**
 - भारतीय और विदेशी भाषाओं में प्रसारित, यह दूरदर्शन और OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।
 - इसका शुभारंभ गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान हुआ।
- **सांस्कृतिक प्रभाव:**
 - यह श्रृंखला बच्चों और वयस्कों दोनों को भारत की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर में रुचि लेने के लिए प्रेरित करती है।

WAVES शिखर सम्मेलन: भारत की रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन 2025 में, भारत **विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन (WAVES)** की मेजबानी करेगा, जिसे मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए "दावोस" के समान माना जा रहा है।

- **रचनाकारों के लिए मंच:**
 - इसमें बॉलीवुड, क्षेत्रीय सिनेमा, टीवी, एनीमेशन, गेमिंग और एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी क्षेत्र के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
 - यह भारत की क्रिएटर इकोनॉमी को \$5 ट्रिलियन के आर्थिक दृष्टिकोण में योगदान देने का अवसर प्रदान करेगा।
- प्रधानमंत्री ने भारत को वैश्विक सामग्री केंद्र के रूप में स्थापित करने की संभावना को रेखांकित करते हुए रचनाकारों को इस परिवर्तनकारी सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया।

भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रचार

- **मिस्र में कला:** 23,000 से अधिक मिस्री छात्रों ने भारतीय संस्कृति और ऐतिहासिक संबंधों को चित्रित करने वाली एक चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया।

- एक दिव्यांग कलाकार द्वारा बनाई गई ताजमहल की पेंटिंग ने भारत के प्रभाव को दर्शाया।

पैराग्वे में आयुर्वेद:

- आयुर्वेद की प्रशंसक एरिका ह्यूबर ने भारतीय दूतावास में परामर्श प्रदान करके दक्षिण अमेरिका में आयुर्वेद के लाभों को बढ़ावा दिया।

फिजी में तमिल भाषा:

- 80 वर्षों में पहली बार फिजी में भारत समर्थित तमिल शिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया गया, जो भारत की प्राचीनतम भाषा के प्रति वैश्विक प्रशंसा का प्रतीक है।

बस्तर ओलंपिक: खेलों में क्रांति

एक क्षेत्र जो कभी संघर्ष के लिए जाना जाता था, वहां बस्तर ओलंपिक खेलों ने खेलों के माध्यम से जीवन को बदल दिया है।

भागीदारी और प्रभाव:

- सात जिलों के 1.65 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने तीरंदाजी, फुटबॉल और कबड्डी जैसे खेलों में भाग लिया।
- पुनेम सन्ना जैसे खिलाड़ियों की कहानियां प्रेरणा देती हैं, जिन्होंने व्हीलचेयर रेसर के रूप में पदक जीते।

आशा का प्रतीक:

- जंगली जल भैंसा और हिल मैना जैसे शुभंकर बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- इस आयोजन ने शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक एकता दोनों को प्रोत्साहित किया है।

स्वास्थ्य उपलब्धियां: मलेरिया और कैंसर

मलेरिया पर विजय:

- 2015-2023 के बीच मलेरिया के मामलों और मृत्यु में 80% की कमी आई (WHO रिपोर्ट)।
- जोरहाट (असम) में जन भागीदारी और कुरुक्षेत्र (हरियाणा) में जागरूकता अभियानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

कैंसर उपचार की उपलब्धि:

- आयुष्मान भारत योजना के तहत 90% कैंसर रोगियों को समय पर उपचार मिला।
- बढ़ती जागरूकता और वित्तीय सहायता ने कैंसर देखभाल में भारत के दृष्टिकोण को बदल दिया।

कालाहांडी में कृषि परिवर्तन

ओडिशा के कालाहांडी में "सब्जी क्रांति" किसान उत्पादक संघ (FPO) के नेतृत्व में आजीविकाओं को पुनर्जीवित कर रही है।

आर्थिक विकास:

- 200 से अधिक किसान, जिनमें 45 महिलाएं शामिल हैं, टमाटर और करेला जैसी फसलें उगा रहे हैं।
- FPO का वार्षिक कारोबार ₹1.5 करोड़ से अधिक है।

सफलता के पाठ:

- आधुनिक खेती तकनीकों और सामूहिक प्रयासों से समृद्धि को बढ़ावा मिल रहा है।

चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए विस्तृत आंकड़े प्रकाशित किए

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए विस्तृत आंकड़े जारी किए, जिसमें 42 सांख्यिकीय रिपोर्ट शामिल हैं। मतदान में वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें 64.64 करोड़ वोट पड़े। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में 7.43% की वृद्धि हुई, और महिलाओं व तीसरे लिंग के मतदाताओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 10.53 लाख हो गई, और नामांकनों की संख्या 12,459 तक पहुंच गई।

महिला मतदाता अब कुल मतदाता संख्या का 48.62% हैं, और चुनाव लड़ने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़कर 800 हो गई। समावेशी चुनावों में तीसरे लिंग और दिव्यांगजन (PwD) मतदाताओं की संख्या में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

राष्ट्रीय दलों ने वैध वोटों का 63.35% प्राप्त किया, जबकि स्वतंत्र उम्मीदवारों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत सामान्य रहा। 3,921 स्वतंत्र प्रत्याशियों में से केवल 7 को विजय प्राप्त हुई।

नीचे निष्कर्षों का विस्तृत विवरण दिया गया है

निर्वाचक एवं मतदाता

Electors and Voters	
Registered Electors	
Year	Total Voters
2019	91,19,50,734
2024	97,97,51,847
Votes Polled	
Total	64.64 crore in 2024 compared to 61.4 crore in 2019.
EVM + Postal Votes	64,64,20,869
EVM Votes	64,21,39,275
Male	32,93,61,948
Female	31,27,64,269
Third Gender	13,058
Postal Ballots	42,81,594
Turnout Highlights	
Highest Turnout	Dhubri (Assam) – 92.3%
Lowest Turnout	Srinagar (J&K) – 38.7% (up from 14.4% in 2019)
Parliamentary Constituencies (PCs) with voting percentages below 50%	11
NOTA Votes	63,71,839 (0.99%), down from 1.06% in 2019.
Transgender Voter Turnout	27.09%, almost double from 14.64% in 2019.

2. मतदान केंद्र

Polling Stations	
Number of Polling Stations	
2019	10,37,848
2024	10,52,664
Increase Percentage	14,816 stations
Repolling	Only 40 polling stations (0.0038%), compared to 540 in 2019.
Electors per Polling Station	931 (on average).
States with the Most/Least Polling Stations	Highest: Uttar Pradesh (1,62,069 PS) Lowest: Lakshadweep (55 PS)
PCs (Parliamentary Constituency) With	Fewer than 1,000 PS (Polling Stations): 11 PCs More than 3,000 PS: 3 PCs
States with Highest Increase in Polling Stations	Bihar: 4,739 new PS West Bengal: 1,731 new PS

3. नामांकन और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार

Nominations and Contesting Details	
Nominations Filed	
2019	11,692
2024	12,459
Highest Nominations in a PC	114 in Malkajgiri (Telangana)
Lowest Nominations in a PC	3 in Dibrugarh (Assam)
Contesting Candidates	
2019	8,054 candidates
2024	8,360 candidates (after rejection and withdrawal)

BANK MAHAPACK PLUS

For IBPS, SBI, SIDBI, RBI
Grade B, +5 More

Selection Ka Saathi

4. महिला मतदाता और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार

Women Electors and Contesting Candidates	
Women Registered Electors	
2019	43,85,37,911
2024	47,63,11,240
Female Electorate Share	
2019	48.09%
2024	48.62%
States with Highest Female Elector Percentage	Puducherry: 53.03% Kerala: 51.56%
Female Electors per 1,000 Male Electors	946 in 2024, up from 926 in 2019
Voting Patterns	
Female Voter Turnout Rate (VTR)	65.78% (excluding Surat)
Male Voter Turnout	65.55%
PCs with Highest Female VTR	Dhubri (Assam): 92.17% Tamluk (West Bengal): 87.57%
Women Contesting Candidates	
2024	800 (up from 726 in 2019)
States with Most Female Contesting Candidates	Maharashtra: 111 Uttar Pradesh: 80 Tamil Nadu: 77
PCs with No Female Contesting Candidates	152 out of 543 PCs

5. समावेशी चुनाव

Inclusive Elections	
Third Gender Electors	
2024	48,272 (up from 39,075 in 2019)
State with Highest Third Gender Electors	Tamil Nadu (8,467)
Transgender Voter Turnout	27.09% (up from 14.64% in 2019)
Persons with Disabilities (PwD) Electors	
2024	90,28,696 (up from 61,67,482 in 2019)
Overseas Electors	
2019	99,844
2024	1,19,374 (Male: 1,06,411; Female: 12,950; Third Gender: 13)

6. चुनाव परिणाम

Election Results	
National Parties	6 participated, securing 63.35% of total valid votes.
Independent Candidates	3,921 contested; only 7 elected in 2024
Vote share of Independents	2.79% of total valid votes
Deposits Forfeited	Total: 7,190 candidates forfeited, up from 6,923 in 2019
Uncontested PC	Surat (Gujarat)
Independent Female Candidates	279

मुख्य बिंदु: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के आंकड़े

रिपोर्ट का अवलोकन

- लोकसभा चुनाव: 42 विस्तृत सांख्यिकीय रिपोर्ट।
- राज्य विधानसभा चुनाव: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम के लिए 14 रिपोर्ट।

उद्देश्य

- भारत की चुनावी प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ाना।
- चुनाव से संबंधित डेटा में अधिकतम पारदर्शिता और खुलासा सुनिश्चित करना।
- विभिन्न हितधारकों के लिए विस्तृत चुनावी डेटा की पहुंच को सरल बनाना।

डेटा कवरेज

- मतदाता विवरण: लोकसभा/विधानसभा क्षेत्र और राज्यवार मतदाता आंकड़े।
- मतदान केंद्र: मतदान केंद्रों की संख्या और उनका वितरण।
- मतदान प्रतिशत: राज्य और लोकसभा क्षेत्रों के आधार पर मतदान आंकड़े।

पार्टी प्रदर्शन

- पार्टीवार वोट शेयर।
- राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियों का प्रदर्शन।
- पंजीकृत अपरिचित राजनीतिक दलों (RUPPs) का विश्लेषण।

लैंगिक अंतर्दृष्टि

- लिंग आधारित मतदान व्यवहार।
- राज्यों में महिला मतदाताओं की भागीदारी।

क्षेत्रीय और निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी

- क्षेत्रीय विविधताएँ।
- निर्वाचन क्षेत्रवार डेटा सारांश और विस्तृत परिणाम।
- विजेता उम्मीदवारों का विश्लेषण।

लक्षित दर्शक

- शोधकर्ता और विश्लेषक: चुनावी रुझानों का गहन अध्ययन कर सकते हैं।
- नीतिनिर्माता: व्यावहारिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- पत्रकार और आम जनता: चुनावी प्रक्रिया और परिणामों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।

महत्व

- चुनाव प्रक्रिया की ईमानदारी और विश्वास बनाए रखने के लिए ECI के मिशन को मजबूत करता है।
- भारत के लोकतंत्र को सुदृढ़ करता है, जिससे सूचित चर्चाओं और निर्णयों को बढ़ावा मिलता है।
- चुनाव अध्ययन में डेटा आधारित विश्लेषण को प्रोत्साहित करता है।

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा

युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2024 के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों, कोचों, विश्वविद्यालयों और संस्थाओं को मान्यता दी गई है। इन पुरस्कारों का वितरण भारत के राष्ट्रपति द्वारा 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा। इन पुरस्कारों का उद्देश्य खेल के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए समर्पण, प्रदर्शन और प्रगति को प्रोत्साहित और मान्यता प्रदान करना है।

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता

1. मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024

प्रदान का उद्देश्य: पिछले चार वर्षों में खेलों में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार।

Sr. No	Name of Recipient	Discipline
1	Shri Gukesh D	(Chess)
2	Shri Harmanpreet Singh	(Hockey)
3	Shri Praveen Kumar	(Para-Athletics)
4	Ms. Manu Bhaker	(Shooting)

2. खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2024

दिया जाता है: खेलों में उत्कृष्टता और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन दिखाने के लिए दिया जाता है।

Sr. No	Name of Recipient	Discipline
1	Ms. Jyothi Yarraji	(Athletics)
2	Ms. Annu Rani	(Athletic)
3	Ms. Nitu	(Boxing)
4	Ms. Saweety	(Boxing)
5	Ms. Vantika Agrawal	(Chess)
6	Ms. Salima Tete	(Hockey)
7	Shri Abhishek	(Hockey)
8	Shri Sanjay	(Hockey)
9	Shri Jarmanpreet Singh	(Hockey)
10	Shri Sukhjeet Singh	(Hockey)
11	Shri Rakesh Kumar	(Para-Archery)
12	Ms. Preeti Pal	(Para-Athletics)

Sr. No	Name of Recipient	Discipline
13	Ms. Jeevanji Deepthi	(Para-Athletics)
14	Shri Ajeet Singh	(Para-Athletics)
15	Shri Sachin Sarjerao Khilari	(Para-Athletics)
16	Shri Dharambir	(Para-Athletics)
17	Shri Pranav Soorma	(Para-Athletics)
18	Shri H Hokato Sema	(Para-Athletics)
19	Ms. Simran	(Para-Athletics)
20	Shri Navdeep	(Para-Athletics)
21	Shri Nitesh Kumar	(Para-Badminton)
22	Ms. Thulasimathi Murugesan	(Para-Badminton)
23	Ms. Nithya Sre Sumathy Sivan	(Para-Badminton)
24	Shri Sajan Prakash	(Swimming)
25	Shri Aman	(Wrestling)
26	Ms. Manisha Ramadass	(Para-Badminton)
27	Shri Kapil Parmar	(Para-Judo)
28	Ms. Mona Agarwal	(Para-Shooting)
29	Ms. Rubina Francis	(Para-Shooting)
30	Shri Swapnil Suresh Kusale	(Shooting)
31	Shri Sarabjot Singh	(Shooting)
32	Shri Abhay Singh	(Squash)

3. खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार (आजीवन) 2024

इसके लिए दिया जाता है: सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है जो खेलों को बढ़ावा देने में योगदान देना जारी रखते हैं।

Sr. No	Name of Recipient	Discipline
1	Shri Sucha Singh	(Athletics)
2	Shri Murlikant Rajaram Petkar	(Para-Swimming)

4. खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024

इसके लिए दिया जाता है: कोचिंग में निरंतर उत्कृष्टता और एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए सम्मानित किया जाता है।

नियमित श्रेणी

Sr. No	Name of Recipient	Discipline
1	Shri Subhash Rana	(Para-Shooting)
2	Ms. Deepali Deshpande	(Shooting)
3	Shri Sandeep Sangwan	(Hockey)

लाइफटाइम श्रेणी

Sr. No	Name of Recipient	Discipline
1	Shri S Muralidharan	(Badminton)
2	Shri Armando Agnelo Colaco	(Football)

5. राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार

इसके लिए दिया जाता है: देश में खेलों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्थाओं को दिया जाता है।

Sr. No	Name of the Entity
1	Physical Education Foundation of India

6. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (MAKA) ट्रॉफी 2024

इसके लिए दिया जाता है: खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाता है।

Sr. No	Position	Name of University
1	Overall Winner University	Chandigarh University
2	1st Runner Up University	Lovely Professional University, (PB)
3	2nd Runner Up University	Guru Nanak Dev University, Amritsar

राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में

मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार

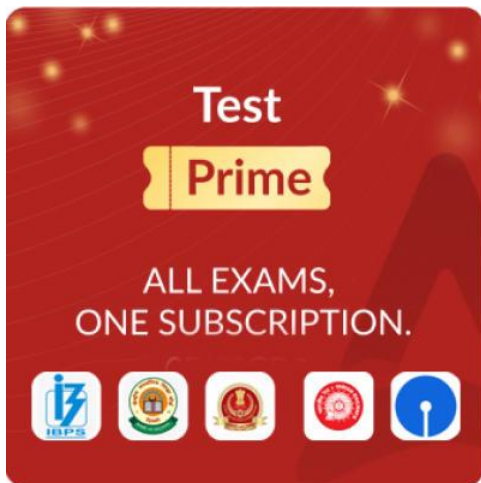
यह खेल के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।

अर्जुन पुरस्कार

खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है।

अर्जुन पुरस्कार (आजीवन योगदान)

उन खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है जो सेवानिवृत्ति के बाद भी खेलों में योगदान देते रहते हैं।



द्विगाचार्य पुरस्कार

उन कोचों को सम्मानित करता है जिन्होंने लगातार एथलीटों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में मदद की है।

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (MAKA) ट्रॉफी

किसी भी विश्वविद्यालय को खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रदान की जाती है।

चयन प्रक्रिया

- इन पुरस्कारों के लिए आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे।
- खिलाड़ियों, कोचों और संस्थाओं ने एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से स्वयं आवेदन किया।
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वी. रामासुब्रमणियन की अध्यक्षता वाली एक समिति ने, जिसमें eminent खिलाड़ी, खेल पत्रकार और प्रशासक शामिल थे, आवेदनों का मूल्यांकन किया और विजेताओं का चयन किया।

महत्व

ये पुरस्कार खेल उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने में व्यक्तियों और संस्थानों के महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाते हैं और भविष्य की पीढ़ियों के एथलीटों और खेल पेशेवरों को प्रेरित करने का लक्ष्य रखते हैं।

कैबिनेट ने किसानों के जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने के लिए सात प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी

2 सितंबर 2024 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सात महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी, जिनकी कुल वित्तीय लागत ₹13,966 करोड़ है।

1. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन (₹2,817 करोड़)

यह मिशन तकनीक का उपयोग करके किसानों के जीवन में सुधार लाने और एक मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने का प्रयास करता है।

मुख्य घटक:

- **एग्री स्टैक:**
 - **किसान रजिस्ट्री:** किसानों का व्यापक डेटाबेस।
 - **गांव भूमि मानचित्र रजिस्ट्री:** गांवों के डिजिटल भूमि मानचित्र।
 - **फसल बोने की रजिस्ट्री:** विभिन्न क्षेत्रों में बोई गई फसलों का दस्तावेजीकरण।
- **कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली:**
 - **भौगोलिक डेटा:** कृषि योजना के लिए सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग।
 - **सूखा/बाढ़ निगरानी:** मौसम से संबंधित घटनाओं की रीयल-टाइम ट्रैकिंग।
 - **जलवायु डेटा:** सटीक मौसम पूर्वानुमान तक पहुंच।
 - **ग्राउंडवॉटर/जल उपलब्धता डेटा:** जल संसाधनों की जानकारी।
 - **फसल उपज और बीमा के लिए मॉडलिंग:** पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण।
 - इस मिशन का उद्देश्य AI और बिग डेटा जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके किसानों को बाजार से जोड़ना और मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नई जानकारी प्रदान करना है।

2. खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान (₹3,979 करोड़)

यह पहल किसानों को जलवायु लचीलापन प्रदान करने और 2047 तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

मुख्य स्तंभ:

- **अनुसंधान और शिक्षा:** कृषि अनुसंधान और शिक्षा को आगे बढ़ाना।
- **प्लांट जेनेटिक रिसोर्स प्रबंधन:** पौधों के आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण।
- **फसल सुधार:** खाद्य और चारे वाली फसलों की गुणवत्ता और उपज को बढ़ाना।
- **दाल और तिलहन फसलों का सुधार:** उच्च उपज देने वाली किस्मों का विकास।
- **वाणिज्यिक फसलों में सुधार:** उत्पादकता बढ़ाना।
- **कीट, सूक्ष्मजीव, परागणकर्ताओं पर अनुसंधान:** कृषि के लिए लाभकारी जीवों का अध्ययन।
- इस योजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान और कृषि पद्धतियों को स्थायी बनाना है।

3. कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना (₹2,291 करोड़)

यह उपाय कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को आधुनिक चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- **शोध और शिक्षा का आधुनिकीकरण:** पाठ्यक्रम और अनुसंधान विधियों को अपडेट करना।
- **नई शिक्षा नीति 2020 के साथ संरेखण:** अंतःविषय दृष्टिकोण को शामिल करना।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** डिजिटल DPI, AI, बिग डेटा और रिमोट सेंसिंग का उपयोग।
- **प्राकृतिक खेती और जलवायु लचीलापन:** स्थायी खेती को बढ़ावा देना।

4. पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को सुदृढ़ बनाना (₹1,702 करोड़)

इस योजना का उद्देश्य पशुपालन और डेयरी से किसानों की आय बढ़ाना है।

मुख्य क्षेत्र:

- पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु चिकित्सा शिक्षा।
- डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास।
- पशु आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन।
- पशु पोषण और छोटे पशुओं का विकास।

5. उद्यानिकी का स्थायी विकास (₹860 करोड़)

इस पहल का उद्देश्य किसानों की आय को विभिन्न उद्यानिकी फसलों से बढ़ाना है।

मुख्य फसलें:

- उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, और समशीतोष्ण फसलें।
- जड़, कंद, बल्ब, और शुष्क फसलें।
- सब्जी, पुष्प और मशरूम फसलें।
- मसाले, औषधीय और सुगंधित पौधे।

6. कृषि विज्ञान केंद्र को सुदृढ़ करना (₹1,202 करोड़)

इस पहल का उद्देश्य किसानों को ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की क्षमता को बढ़ाना है।

7. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (₹1,115 करोड़)

इस योजना का लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना है, जो दीर्घकालिक कृषि व्यवहार्यता और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है।

One Nation One Subscription: क्या है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम

केंद्र सरकार ने नए साल पर स्टूडेंट्स के लिए "वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन" (ONOS) स्कीम को लॉन्च किया है। इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से नवंबर 2024 में ही मंजूरी दे दी गई थी जिसके बाद अब 1 जनवरी को इसको लॉन्च करके रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए गए हैं। यह योजना देशभर के लिए शुरू की गई है ऐसे में देश के हर कोने से छात्र इसका लाभ उठाने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में छात्रों और रिसर्चर्स के लिये उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाना है। इस योजना से टियर-2 और टियर-3 शहरों में रहने वाले छात्र भी आसानी से अपनी पहुंच बना सकेंगे। इस योजना को दो चरणों में लागू किया जायेगा जिसके लिए 6 हजार करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।

क्या है इस योजना का लाभ

इस योजना के तहत IITs समेत सभी सरकारी वित्त पोषित हायर इंस्टीट्यूट्स के लगभग 1.80 करोड़ छात्रों को सीधे फायदा होगा। छात्र इस योजना के तहत 13400 से भी अधिक अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स एक ही जगह प्राप्त कर सकेंगे। इस पोर्टल पर 6300 संस्थान रजिस्टर्ड होंगे। इसमें IIT और NIT जैसे संस्थान भी शामिल होंगे। यह पोर्टल पूरी तरह से डिजिटल होगा जहां से स्टूडेंट्स अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोध और जर्नल्स का उपयोग अपने पढ़ाई के लिए कर पाएंगे।

योजना के बारे में

- दो चरणों में लागू की जाएगी One Nation One Subscription (ONOS) स्कीम।
- योजना के लिए 6000 करोड़ रुपये का बजट किया गया है तय।
- 13400 से भी अधिक अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स होंगे उपलब्ध।
- देशव्यापी रूप से होगी इस स्कीम की पहुंच।
- IITs समेत सभी सरकारी सरकार द्वारा फंड प्राप्त हायर इंस्टीट्यूट्स के लगभग 1.80 करोड़ छात्रों को होगा फायदा।

पहले चरण में इन विषयों के शोध

इस योजना के तहत पहले चरण में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिकल, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, और ह्यूमैनिटीज विषयों के लिए 13400 से भी अधिक जर्नल्स एवं शोध उपलब्ध होंगे। इसका दूसरा चरण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के आधार पर आगे बढ़ाया जायेगा। इस योजना से रिसर्चर्स के लिए संसाधनों में तेजी से सुधार आएगा।

भारत ने UNFCCC को चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की

भारत ने 30 दिसंबर, 2024 को **संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन (UNFCCC)** को अपना चौथा द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (BUR-4) प्रस्तुत किया। यह रिपोर्ट तीसरी राष्ट्रीय संचार (TNC) पर आधारित है और 2020 के लिए भारत की राष्ट्रीय ग्रीनहाउस गैस (GHG) सूची का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। इसमें राष्ट्रीय परिस्थितियों, शमन कार्यों, और संबंधित वित्त, प्रौद्योगिकी एवं क्षमता निर्माण की जरूरतों पर महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए सतत विकास में भारत के नेतृत्व को रेखांकित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री **नरेंद्र मोदी** की आर्थिक प्रगति और जलवायु कार्रवाई के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रतिबद्धता पर बल दिया।

BUR-4 रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

1. 2020 की GHG सूची

- **कुल GHG उत्सर्जन (2020):**
 - **LULUCF (भूमि उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी) के बिना:** 2,959 मिलियन टन CO₂ समतुल्य।
 - **LULUCF के साथ:** 2,437 मिलियन टन CO₂ समतुल्य।
- **उत्सर्जन में कमी:**
 - 2019 की तुलना में कुल GHG उत्सर्जन में 7.93% की गिरावट।

2. क्षेत्रीय उत्सर्जन में योगदान

- **ऊर्जा क्षेत्र:** 75.66%
- **कृषि:** 13.72%
- **औद्योगिक प्रक्रियाएं और उत्पाद उपयोग (IPPU):** 8.06%
- **कचरा:** 2.56%

3. वन और वृक्ष आवरण का योगदान

- वनों और वृक्ष आवरण ने 2020 में **522 मिलियन टन CO₂** अवशोषित किया, जिससे कुल CO₂ उत्सर्जन में 22% की कमी आई।
- भारत का वन और वृक्ष आवरण **कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17%** है।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्य में उपलब्धियां

1. आर्थिक वृद्धि और उत्सर्जन को अलग करना

- 2005 से 2020 के बीच, भारत की GDP की उत्सर्जन तीव्रता में **36%** की कमी आई, जो 33-35% के लक्ष्य से अधिक है।

2. नवीकरणीय ऊर्जा में प्रगति

- अक्टूबर 2024 तक, स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी **46.52%** तक पहुंच गई।
- **नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (बड़े हाइड्रो को छोड़कर):** 156.25 GW (मार्च 2014 में 35 GW से 4.5 गुना वृद्धि)।
- **कुल स्थापित नवीकरणीय क्षमता (बड़े हाइड्रो सहित):** 203.22 GW।

3. अतिरिक्त कार्बन सिंक

- 2005 से 2021 के बीच, भारत ने वनों और वृक्ष आवरण में वृद्धि के माध्यम से **2.29 बिलियन टन CO₂** समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया।

जलवायु कार्रवाई के प्रति प्रतिबद्धता

- ऐतिहासिक और वर्तमान वैश्विक उत्सर्जन में न्यूनतम योगदान देने के बावजूद, भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्रिय बना हुआ है।
- भारत ने **समानता और सामान्य लेकिन भिन्न जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC)** के सिद्धांतों के साथ UNFCCC और पेरिस समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है।

सरकारी ऋण राहत योजना पर आरबीआई के दिशानिर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सरकार की **ऋण राहत योजना (Government Debt Relief Scheme)** में भाग लेने वाले उधारदाताओं के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य वित्तीय संकट का सामना कर रहे उधारकर्ताओं को संरचित राहत प्रदान करना है। यह पहल भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता बढ़ाने और आर्थिक पुनरुद्धार को समर्थन देने के RBI के प्रयासों के अनुरूप है।

दिशानिर्देशों का मुख्य सारांश

RBI के दिशानिर्देश उधारदाताओं के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं, जिससे वे वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे उधारकर्ताओं को ऋण राहत प्रदान कर सकें। योजना का उद्देश्य ऋणों का पुनर्गठन सुनिश्चित करना है, जिससे उधारकर्ताओं को सहायता मिल सके और वित्तीय प्रणाली की अखंडता बनी रहे।

योजना के प्रमुख घटक

1. पात्रता मानदंड

- यह योजना उन उधारकर्ताओं को लक्षित करती है जिन्होंने **लगातार पुनर्भुगतान** का प्रदर्शन किया है लेकिन **अप्रत्याशित परिस्थितियों** के कारण वर्तमान में वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

2. पुनर्गठन ढांचा

- उधारदाताओं को अनुमति है कि वे निम्नलिखित तरीकों से ऋण पुनर्गठन कर सकते हैं:
 - पुनर्भुगतान अवधि बढ़ाना।
 - ब्याज दरों में कमी करना।
 - ऋण का एक हिस्सा **इक्विटी (शेयर)** में परिवर्तित करना।
- पुनर्गठन विशेष शर्तों के अधीन होगा।

3. नियामकीय निगरानी

- RBI योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिशानिर्देशों का अनुपालन हो और वित्तीय स्थिरता बनी रहे।

ऐतिहासिक संदर्भ

- यह पहल RBI द्वारा उधारकर्ताओं के वित्तीय तनाव को संबोधित करने के लिए पहले उठाए गए कदमों पर आधारित है।
- विशेष रूप से, 2016 में, **हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (HCC)** को **सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेट्स एसेट्स (S4A)** योजना के तहत ऋण राहत प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनने का गौरव प्राप्त हुआ।
- इस योजना के तहत बैंकों को कंपनी के ऋण का एक हिस्सा **इक्विटी या डिबेंचर** में बदलने की अनुमति दी गई थी।

उधारदाताओं और उधारकर्ताओं के लिए प्रभाव

1. उधारदाताओं के लिए:

- दिशानिर्देश संकटग्रस्त संपत्तियों (Distressed Assets) के प्रबंधन के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।
- यह उधारदाताओं को उधारकर्ताओं को राहत देने की अनुमति देता है जबकि उनके वित्तीय हित सुरक्षित रहते हैं।

2. उधारकर्ताओं के लिए:

- योजना वित्तीय पुनर्प्राप्ति (Financial Recovery) का मार्ग प्रदान करती है।
- यह व्यवसायों और व्यक्तियों को उनके ऋणों का पुनर्गठन करने और दिवालियापन के तत्काल खतरे के बिना अपने संचालन जारी रखने की अनुमति देती है।

राज्य वित्त 2024-25 पर RBI की रिपोर्ट

RBI की हालिया रिपोर्ट ने महामारी के बाद राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण सुधारों को रेखांकित किया है, साथ ही उन क्षेत्रों की पहचान की है, जहां और सुधार की आवश्यकता है।

वित्तीय समेकन में उपलब्धियां

- **सकल वित्तीय घाटा (GFD):**
2022-23 और 2023-24 में राज्यों ने अपने समेकित GFD को GDP के 3% के भीतर सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। 2024-25 के लिए यह 3.2% बजट किया गया है।
- **राजस्व घाटा:**
2022-23 और 2023-24 में GDP के 0.2% पर कम स्तर पर बनाए रखा गया।
- **पूंजीगत व्यय:**
यह GDP के 2.4% (2021-22) से बढ़कर 2.8% (2023-24) हुआ और 2024-25 में इसे 3.1% तक बढ़ाने का बजट किया गया है, जो विकासात्मक खर्च पर ध्यान केंद्रित करता है।

ऋण स्तर और दायित्व

- **बकाया दायित्व:**
मार्च 2021 के अंत में GDP के 31% से घटकर मार्च 2024 के अंत में 28.5% हो गया, लेकिन यह महामारी से पहले के स्तर (मार्च 2019 के अंत में 25.3%) से अब भी अधिक है।
- **संभावित दायित्व:**
राज्यों की गारंटी मार्च 2017 में GDP के 2% से बढ़कर मार्च 2023 तक 3.8% हो गई है, जिससे संभावित वित्तीय जोखिम पैदा हो सकता है।

सब्सिडी व्यय

- **बढ़ती सब्सिडी:**
कृषि ऋण माफी और मुफ्त/सब्सिडी सेवाओं जैसे बिजली, परिवहन और गैस सिलेंडरों पर खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
○ उदाहरण: 14 राज्यों ने महिलाओं के लिए आय हस्तांतरण योजनाएं लागू की हैं, जिनकी कुल लागत लगभग ₹2 लाख करोड़ (GDP का 0.6%) है।

बिजली क्षेत्र की चिंताएं

- **डिस्कॉम घाटे:**
2022-23 तक बिजली वितरण कंपनियों ने ₹6.5 लाख करोड़ के घाटे का सामना किया, जो GDP का लगभग 2.4% है। सुधार के कई प्रयासों के बावजूद यह समस्या बनी हुई है।

वित्तीय स्थिरता के लिए सिफारिशें

1. **ऋण समेकन:**
 - ऊंचे ऋण स्तर वाले राज्यों के लिए, RBI ने एक विश्वसनीय रोडमैप की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें स्पष्ट, पारदर्शी और समयबद्ध रणनीतियां हों।
2. **व्यय दक्षता:**
 - परिणाम-आधारित बजटिंग के माध्यम से व्यय दक्षता बढ़ाने और सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की गई है, ताकि उत्पादक व्यय को कम न किया जा सके।
3. **वित्तीय ढांचा सुधार:**
 - जोखिम-आधारित वित्तीय ढांचे को अपनाने, प्रतिकूल चक्रीय नीतियों का प्रावधान करने, और राज्य वित्त आयोगों को मजबूत बनाने की सलाह दी गई है।
 - यह सुधार स्थानीय निकायों को वित्तीय अनुशासन और पर्याप्त धन हस्तांतरण सुनिश्चित करेगा।

सरकार ने WPI आधार वर्ष को अद्यतन करने के लिए समिति गठित की

2 जनवरी, 2025 को भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार वर्ष को 2011-12 से 2022-23 में बदलने के लिए एक 18-सदस्यीय समिति का गठन किया। इस पहल का उद्देश्य **फैक्ट्री-गेट मुद्रास्फीति (Factory-Gate Inflation)** के माप को अधिक सटीक बनाना और पिछले दशक में अर्थव्यवस्था में हुए संरचनात्मक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करना है।

समिति का नेतृत्व और संरचना

- **अध्यक्ष:** नीति आयोग के सदस्य **प्रोफेसर रमेश चंद्र**।
- **सदस्य:** विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ जैसे अर्थशास्त्र, वित्त, और सांख्यिकी, जो संशोधन प्रक्रिया को व्यापक दृष्टिकोण देंगे।

कायदेश (Terms of Reference)

समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

1. **वस्तुओं का चयन:**
 - 2022-23 के आधार वर्ष के लिए WPI और प्रस्तावित उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) में शामिल किए जाने वाले वस्तुओं की पहचान करना।
 - इसमें अर्थव्यवस्था में हुए संरचनात्मक परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाएगा।
2. **मूल्य संग्रह प्रणाली की समीक्षा:**
 - मौजूदा मूल्य संग्रह पद्धति का मूल्यांकन और उसमें सुधार के लिए सिफारिशें देना।
3. **गणना पद्धति (Computational Methodology):**
 - WPI और PPI के लिए उपयुक्त गणना पद्धतियां प्रस्तावित करना।
4. **PPI संकलन पद्धति:**
 - PPI संकलन की अनुमोदित पद्धति का आकलन और उसमें सुधार के लिए सुझाव देना।

5. संक्रमण रोडमैप:

- WPI से PPI में संक्रमण के लिए एक योजना विकसित करना।

6. विश्वसनीयता में सुधार:

- WPI और PPI डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना।
- समिति को अपनी अंतिम रिपोर्ट **18 महीनों के भीतर** प्रस्तुत करनी है।

प्रसंग और प्रभाव

- WPI का पिछला संशोधन 2015 में हुआ था, जब आधार वर्ष को 2004-05 से 2011-12 में अपडेट किया गया था।
- आगामी संशोधन (2022-23) का उद्देश्य महत्वपूर्ण आर्थिक विकासों को शामिल करना है, जैसे कि **सेवा क्षेत्र का विस्तार**, जो अब भारत के कुल आर्थिक उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा बनाता है।
- WPI से PPI में संक्रमण से निर्माता स्तर पर मुद्रास्फीति को अधिक व्यापक रूप से मापने का अवसर मिलेगा, जिसमें **सामान और सेवाएं** दोनों शामिल होंगी।

WPI, CPI और प्रस्तावित PPI के बारे में जानकारी

1. थोक मूल्य सूचकांक (WPI):

WPI उन वस्तुओं के औसत थोक मूल्य को ट्रैक करता है जो उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले उत्पादकों के स्तर पर मौजूद होती हैं।

- क्षेत्र:** केवल वस्तुओं को शामिल करता है, सेवाओं को नहीं।
- डेटा जारी करना:** मासिक रूप से **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DIPP)**, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा।
- कार्य:** नाममात्र GDP को वास्तविक GDP में परिवर्तित करने के लिए डिफ्लेटर के रूप में उपयोग किया जाता है।

2. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI):

CPI खुदरा मुद्रास्फीति को मापता है और उन वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमतों को ट्रैक करता है जो घरों द्वारा उपभोग की जाती हैं।

- क्षेत्र:** उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल।
- डेटा जारी करना:** मासिक रूप से **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)**, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा।
- कार्य:**
 - मुद्रास्फीति प्रबंधन में महत्वपूर्ण।
 - वेतन समायोजन और आर्थिक नीति निर्माण के लिए उपयोग।

3. प्रस्तावित उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI):

PPI एक उभरता हुआ मुद्रास्फीति माप है जो उत्पादन के विभिन्न चरणों पर वस्तुओं और सेवाओं के थोक मूल्य को मापेगा।

- क्षेत्र:** WPI के विपरीत, PPI में **सेवा क्षेत्र** भी शामिल होगा।
- महत्व:**
 - यह अर्थव्यवस्था में मूल्य परिवर्तनों की अधिक पूर्ण तस्वीर प्रदान करेगा।
 - यह **सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स (SNA)** के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है।
- भविष्य की योजना:** WPI से PPI में संक्रमण के लिए एक समर्पित कार्यसमूह उपयुक्त पद्धति पर कार्य कर रहा है।

छात्र नामांकन में गिरावट: यूडीआईएसई+ रिपोर्ट 2023-24

शिक्षा मंत्रालय की **यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+)** रिपोर्ट 2023-24 ने छात्रों के नामांकन में महत्वपूर्ण गिरावट को उजागर किया है। यह बदलाव पिछले वर्षों में देखी गई स्थिर प्रवृत्ति से अलग है।

UDISE+ क्या है?

UDISE+ (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस), 2018-19 में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा विकसित एक ऑनलाइन डेटा संग्रह प्रणाली है।

- यह **मैनुअल कागज-आधारित डेटा संग्रह प्रक्रिया** को बदलने के लिए पेश किया गया था।
- यह डेटा **कैप्चर, मैपिंग और सत्यापन में सुधार** सुनिश्चित करता है।

मुख्य निष्कर्ष

1. कुल नामांकन में गिरावट:

- कुल छात्र नामांकन 2023-24 में घटकर **24.8 करोड़** हो गया।
- यह पिछले वर्षों की तुलना में **1 करोड़ से अधिक की गिरावट** है।
- 2018-19 के 26.02 करोड़ नामांकन** की तुलना में यह **6%** की गिरावट को दर्शाता है।

2. लिंग-आधारित नामांकन रुझान:

- लड़के:**
 - 2018-19 में 13.53 करोड़ से घटकर 2023-24 में **12.87 करोड़**।
 - 4.87%** की गिरावट।
- लड़कियां:**
 - 2018-19 में 12.49 करोड़ से घटकर 2023-24 में **11.93 करोड़**।
 - 4.48%** की गिरावट।

3. क्षेत्रीय भिन्नताएं:

- बिहार:**
 - नामांकन 2018-19 में 2.49 करोड़ से घटकर 2023-24 में **2.13 करोड़**।
 - 35.65 लाख छात्रों की कमी**।
- उत्तर प्रदेश:**
 - नामांकन 2018-19 में 4.44 करोड़ से घटकर 2023-24 में **4.16 करोड़**।
 - 28.26 लाख की कमी**।
- महाराष्ट्र:**
 - नामांकन 2018-19 में 2.32 करोड़ से घटकर 2023-24 में **2.13 करोड़**।
 - 18.55 लाख छात्रों की गिरावट**।

4. स्कूल का बुनियादी ढांचा:

- 90%** से अधिक स्कूलों में बिजली और लिंग-विशिष्ट शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं।
- 57.2%** स्कूलों में कार्यशील कंप्यूटर उपलब्ध हैं।
- 53.9%** स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है।
- 52.3%** स्कूलों में रैंप की व्यवस्था है।

परिणाम और प्रभाव:

- **नामांकन में गिरावट** वर्तमान शैक्षिक नीतियों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाती है।
- यह दर्शाता है कि **लक्षित हस्तक्षेप** की आवश्यकता है, ताकि राज्यों और विभिन्न जनसांख्यिकी में छात्र नामांकन और प्रतिधारण दर को बेहतर बनाया जा सके।
- **UDISE+ से प्राप्त डेटा** भविष्य की रणनीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

National Affairs

- नेपाल के चितवन जिले के सौराहा में 18वां हाथी और पर्यटन महोत्सव आकर्षण का केंद्र बन गया है। चितवन नेशनल पार्क के पास बघमारा इंटरमीडिएट कम्युनिटी फॉरेस्ट में आयोजित यह पाँच दिवसीय महोत्सव क्रिसमस और नए साल के उत्सवों के साथ मेल खाता है। यह महोत्सव 30 दिसंबर को समाप्त होगा और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो अपनी विविध और अनूठी गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। ([Click here to read article](#))
- काम्या कार्तिकेयन, मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा, ने सात महाद्वीपों के सबसे ऊंचे शिखरों को फतह कर इतिहास रच दिया है। काम्या विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं, जिन्होंने यह अद्भुत उपलब्धि हासिल की है। 24 दिसंबर, 2024 को अंटार्कटिका के माउंट विन्सन पर चढ़ाई पूरी कर उन्होंने इस प्रतिष्ठित लक्ष्य को प्राप्त किया। उनका यह कारनामा दृढ़ संकल्प, सहनशक्ति और पर्वतारोहण के प्रति उनकी गहरी रुचि को दर्शाता है। ([Click here to read article](#))
- भारत सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के सेवानिवृत्त होने वाले उन कर्मियों के लिए मानद वरिष्ठ रैंक प्रदान करने की योजना पर विचार कर रही है, जिन्हें संगठनात्मक बाधाओं के कारण पदोन्नति नहीं मिल सकी। इस पहल का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मियों का मनोबल बढ़ाना और उनकी सेवाओं को मान्यता देना है। ([Click here to read article](#))
- Blinkit के सीईओ अल्विंदर धिंदसा ने गुरुग्राम में एक त्वरित एंबुलेंस सेवा की शुरुआत की घोषणा की है, जहां निवासी Blinkit ऐप के माध्यम से एंबुलेंस बुक कर सकते हैं, जो 10 मिनट के भीतर पहुंचेगी। यह पहल शहरी क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा परिवहन की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से की गई है। यह सेवा, जिसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट (BLS) एंबुलेंस शामिल हैं, तेज और विश्वसनीय चिकित्सा सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ([Click here to read article](#))
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) को पूरे भारत के क्षेत्रीय कार्यालयों में सफलतापूर्वक लागू कर दिया है, जिससे पेंशन वितरण में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इस पहल से 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा, जिससे वे देश के किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। ([Click here to read article](#))

- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भारत के पहले कांच के पुल (ग्लास ब्रिज) का उद्घाटन किया, जो कन्याकुमारी में स्थित है। यह पुल विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ता है, जिससे कन्याकुमारी एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में और अधिक आकर्षक बन गया है। तमिलनाडु सरकार द्वारा 37 करोड़ रुपये की परियोजना के तहत निर्मित, यह कांच का पुल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और स्थानीय पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। ([Click here to read article](#))

States in the News

- 25 दिसंबर को "सुशासन दिवस" के अवसर पर, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने SWAR (Speech and Written Analysis Resource) प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। यह पहल नागरिकों के लिए भाषा बाधाओं को समाप्त कर संचार और पहुंच को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नागरिक केंद्रित इस पहल का उद्देश्य राज्य में जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाना है। यह प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भाषिणी टीम के सहयोग से विकसित किया गया है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करता है ताकि सरकारी सेवाओं को अधिक समावेशी बनाया जा सके। ([Click here to read article](#))
- 2 जनवरी, 2025 को राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर ने केरल के 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। यह समारोह तिरुवनंतपुरम स्थित राजभवन में आयोजित किया गया। उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान का स्थान लिया है, जिन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जमदार ने शपथ दिलाई। इस अवसर पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ([Click here to read article](#))
- अरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली, उन्होंने राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर का स्थान लिया, जिन्हें केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। यह समारोह राज भवन में आयोजित किया गया, जहां पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां मौजूद थीं। ([Click here to read article](#))
- असम में हाथियों की आबादी में वृद्धि हुई है और यह संख्या 5,828 हो गई है। इसकी घोषणा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने की, जिसमें बताया गया है कि असम वन विभाग ने हाल ही में राज्य में 2024 के लिए हाथियों की आबादी का अनुमान पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने सरमा ने कहा कि हाल ही में असम में 2024 के लिए हाथियों की आबादी का अनुमान लगाया है। 7 साल बाद किए गए इस सर्वेक्षण में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर 5,828 हो गई है। उन्होंने हाथियों के संरक्षण में वन विभाग के प्रयासों की भी प्रशंसा की। यह सर्वेक्षण सात साल के अंतराल के बाद किया गया था। ([Click here to read article](#))

International Affairs

- सुफी संत हज़रत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स शुरू हो चुका है, जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। इस साल, पारंपरिक ध्वजारोहण समारोह शनिवार, 28 दिसंबर 2024 को अजमेर स्थित दरगाह ख्वाजा साहब में आयोजित किया जाएगा। श्रद्धेय संत की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला वार्षिक उर्स श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता है, जिसमें संत की मजार पर उत्सव और प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं। ([Click here to read article](#))
- दक्षिण कोरिया में 27 दिसंबर, 2024 को राजनीतिक संकट और गहरा गया जब संसद ने कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू को महाभियोग करने के पक्ष में मतदान किया। यह घटनाक्रम 14 दिसंबर, 2024 को राष्ट्रपति यून सुक-योल के महाभियोग के बाद हुआ, जो 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लागू करने के कारण हुआ था। हान, राष्ट्रपति यून के निलंबन के बाद से कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर रहे थे, लेकिन संविधान न्यायालय के तीन न्यायाधीशों को नियुक्त करने से इनकार करने के कारण विपक्ष ने उनके महाभियोग की मांग की। यह दक्षिण कोरिया के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि यह पहली बार है जब किसी कार्यवाहक राष्ट्रपति को महाभियोग का सामना करना पड़ा है। ([Click here to read article](#))
- चीन ने CR450, दुनिया की सबसे तेज़ हाई-स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप, का परिचय दिया है, जिसमें परीक्षण गति 450 किमी/घंटा तक पहुंच गई है। यह वर्तमान CR400 फुक्सिंग ट्रेनों (350 किमी/घंटा) को पार करते हुए रेल प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो गति के साथ-साथ ऊर्जा दक्षता, सुरक्षा और यात्रियों की आरामदायकता में भी सुधार करता है। यह नवाचार चीन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ मेल खाता है, जिसके तहत 2035 तक अपने हाई-स्पीड रेल नेटवर्क को 70,000 किमी तक विस्तार देने की योजना है, जिससे यह वैश्विक रेल प्रणालियों में अपनी अगुआई को और मजबूत करेगा। ([Click here to read article](#))
- 1 जनवरी 2025 से प्रभावी, रूस ने अपने पुराने रिज़ॉर्ट शुल्क को बदलते हुए एक नया पर्यटन कर (टूरिस्ट टैक्स) पेश किया है। यह पहल, रूसी टैक्स कोड में संशोधन के माध्यम से लागू की गई है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय पर्यटन अवसरचना को मजबूत करना है। इस योजना के तहत शुरुआती चरण में यात्रियों से उनके आवास की लागत का 1% शुल्क लिया जाएगा, जो 2027 तक बढ़कर 3% हो जाएगा। यह कर होटलों और अन्य आवासों पर लागू होता है, जिसकी लागत अंततः पर्यटकों को वहन करनी होगी। क्षेत्रीय अधिकारियों को इसे स्थानीय कर के रूप में लागू करने की शक्ति दी गई है, जिससे यह रूस के पर्यटन क्षेत्र को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ([Click here to read article](#))
- स्विट्जरलैंड 1 जनवरी, 2025 से विभिन्न क्षेत्रों में कानूनी, आर्थिक, और सामाजिक ढांचों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण बदलाव लागू कर रहा है। इनमें चेहरे को ढंकने पर प्रतिबंध, उत्तराधिकार कानून में सुधार, पेंशन में वृद्धि, और बैंक की सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी को मजबूत करने के उपाय शामिल हैं। ये बदलाव यूरोपीय मानदंडों के साथ बढ़ती सामंजस्यता और पिछले वित्तीय संकटों के प्रति प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं। ([Click here to read article](#))

- भारत-नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास “सूर्य किरण” के 18वें संस्करण की शुरुआत 29 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सालझांडी में हुई है। इस वार्षिक अभ्यास का उद्देश्य जंगल युद्ध, पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद-रोधी अभियानों, और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत मानवीय सहायता व आपदा प्रबंधन में सहयोग को बढ़ाना है। ([Click here to read article](#))
- चीन वर्तमान में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि का सामना कर रहा है, जिससे संभावित स्वास्थ्य संकट की चिंताएँ बढ़ गई हैं, जो COVID-19 महामारी की याद दिला रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार, अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, और HMPV, इन्फ्लूएंजा ए, माइकोप्लाज़्मा न्यूमोनिया और COVID-19 जैसे कई वायरस इस स्थिति में योगदान दे रहे हैं। हालांकि, कुछ आपातकालीन स्थिति के दावों के बावजूद, चीनी अधिकारियों से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ([Click here to read article](#))
- 1 जनवरी 2025 को पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में दो साल के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया। यह पाकिस्तान का 15-सदस्यीय परिषद में आठवां कार्यकाल है, जिसमें उसने जापान को एशियाई प्रतिनिधि के रूप में प्रतिस्थापित किया। राजदूत मुनिर अकरम ने वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में पाकिस्तान की “सक्रिय और रचनात्मक” भूमिका निभाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। ([Click here to read article](#))

Books and Authors

- केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में पुस्तक ‘जम्मू कश्मीर और लद्दाख श्रू द एजेंस: ए विजुअल नैरेटिव ऑफ कंटिन्यूटीज एंड लिंकेजेस’ का विमोचन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (ICHR) के अध्यक्ष प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। श्री अमित शाह ने पुस्तक की भौगोलिक-सांस्कृतिक एकता को दस्तावेजीकृत करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला और जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के भारत से अटूट संबंध को रेखांकित किया। ([Click here to read article](#))

BANK
MAHAPACK

for all Bank & Insurance
Exams

Selection Ka Saathi

Banking/Economy/Business News

- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने भारत की प्रमुख ऑडियो और वियरेबल्स ब्रांड boAt के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (D2C) और विनिर्माण क्षेत्रों में DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को नवाचार और समर्थन प्रदान करना है। इस सहयोग के माध्यम से स्टार्टअप्स को सलाह, संसाधन, और मार्गदर्शन देकर उन्हें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने में मदद मिलेगी। boAt के औद्योगिक अनुभव और सरकारी समर्थन के साथ, यह पहल भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के लिए तैयार है। ([Click here to read article](#))
- मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने स्वास्थ्य सेवा पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए कर्किनोस हेल्थकेयर का अधिग्रहण किया है। यह अधिग्रहण रिलायंस की सहायक कंपनी रिलायंस स्ट्रैटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड (RSBVL) के माध्यम से पूरा किया गया और कैंसर के निदान, पहचान और उपचार में कंपनी की पहुंच का विस्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ([Click here to read article](#))
- डेलॉइट इंडिया के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025 में 6.5-6.8% की दर से वृद्धि करने का अनुमान है। यह वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू खपत, बुनियादी ढांचा विकास, और डिजिटलीकरण से प्रेरित होगी। FY2026 में यह वृद्धि 6.7-7.3% तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि, भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार विवाद, और वैश्विक तरलता सीमाएं दीर्घकालिक दृष्टिकोण को चुनौती दे सकती हैं। ([Click here to read article](#))
- भारत के FY25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर को 6.6% पर अनुमानित किया गया है। ग्रामीण खपत में पुनरुत्थान, सरकारी खर्च में वृद्धि, और सेवाओं के निर्यात में मजबूती इसके मुख्य कारक हैं। हालांकि, FY24 की पहली छमाही (H1 FY24) में 8.2% की वृद्धि के मुकाबले FY25 की पहली छमाही (H1 FY25) में यह घटकर 6% हो गई है। ([Click here to read article](#))
- भारत में दिसंबर 2024 में जीएसटी संग्रह वृद्धि 7.3% वर्ष-दर-वर्ष (YoY) रही, जिसमें कुल राजस्व ₹1.77 लाख करोड़ रहा, जबकि दिसंबर 2023 में यह ₹1.65 लाख करोड़ था। यह पिछले तीन महीनों में सबसे धीमी वृद्धि है और छुट्टियों के बाद उपभोक्ता खर्च में थोड़ी गिरावट को दर्शाता है। जीएसटी राजस्व लगातार दस महीनों से ₹1.7 लाख करोड़ से ऊपर बना हुआ है, और दिसंबर तिमाही का औसत ₹1.82 लाख करोड़ रहा, जो वर्ष-दर-वर्ष 8.3% अधिक है। ([Click here to read article](#))
- भारत के कॉफी निर्यात ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, वित्तीय वर्ष 2024 (अप्रैल से नवंबर) के दौरान \$1.14 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचते हुए, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 29% की वृद्धि को दर्शाता है। इस वृद्धि का श्रेय रोबस्टा कॉफी की बढ़ती वैश्विक मांग और ब्राज़ील और वियतनाम जैसे प्रमुख उत्पादक देशों द्वारा सामना किए जा रहे आपूर्ति श्रृंखला मुद्दों को जाता है। कर्नाटक से मुख्य रूप से उत्पादित भारत की उच्च-गुणवत्ता वाली कॉफी ने प्रीमियम

- वैश्विक बाजारों में अपनी पहचान बनाई है, जिससे यह वृद्धि और तेज़ हो गई है। ([Click here to read article](#))
- भारत ने आर्थिक विकास को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से अलग करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, 2005 से 2020 के बीच जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी हासिल की है। यह प्रगति पेरिस समझौते के तहत देश के जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों के अनुरूप है। ([Click here to read article](#))
- 31 दिसंबर, 2024 तक, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने घोषणा की कि ₹2,000 मूल्यवर्ग के 98.12% बैंक नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं, जिनमें से ₹6,691 करोड़ अभी भी जनता के पास हैं। ([Click here to read article](#))
- नोमुरा ने भारत के वित्तीय वर्ष 2025 की GDP वृद्धि के अपने अनुमान को 6.9% से घटाकर 6.7% कर दिया है। यह संशोधन अप्रैल-जून तिमाही के धीमे विकास दर के आंकड़ों के बाद किया गया, जहां GDP वृद्धि 6.7% दर्ज की गई, जो पिछली तिमाही के 7.8% से कम थी। ([Click here to read article](#))
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) सिस्टम के लिए नाम जांच सुविधा शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य धोखाधड़ी और त्रुटियों को कम करना है। यह सुविधा, जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और इमीडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS) जैसी सेवाओं के समान है, प्रेषक को लेनदेन शुरू करने से पहले लाभार्थी के नाम को सत्यापित करने की अनुमति देगी। ([Click here to read article](#))
- रजत वर्मा, जो वर्तमान में DBS बैंक इंडिया के इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग ग्रुप के प्रमुख हैं, को 1 मार्च 2025 से DBS बैंक इंडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है। यह घोषणा सुरोजित शोम के सेवानिवृत्त होने के बाद की गई है, जो 2015 से इस पद पर थे। वर्मा की नियुक्ति, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मंजूरी के अधीन है, DBS इंडिया के लिए एक नए चरण की शुरुआत है क्योंकि बैंक भारत में अपनी विकास यात्रा को जारी रखेगा, जो इसके प्रमुख बाजारों में से एक है। ([Click here to read article](#))
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 2 जनवरी 2025 को अनिवासी भारतीयों (NRIs) के लिए एक टेबलेट आधारित एंड-टू-एंड डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य गैर-निवासी बाहरी (NRE) और गैर-निवासी साधारण (NRO) खातों को खोलने के लिए भौतिक दस्तावेज़ीकरण को समाप्त करना और डिजिटल दस्तावेज़ सत्यापन के माध्यम से खाता खोलने की प्रक्रिया को तेज़ करना है। ([Click here to read article](#))
- RBI की हालिया रिपोर्ट ने महामारी के बाद राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण सुधारों को रेखांकित किया है, साथ ही उन क्षेत्रों की पहचान की है, जहां और सुधार की आवश्यकता है। ([Click here to read article](#))
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और विभिन्न ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से दो नवाचारी जमा योजनाएं शुरू की हैं: 'हर घर लाखपति' और 'एसबीआई पैट्रोन्स'। ([Click here to read article](#))

Appointments/Resignations

- न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन, पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसकी घोषणा 23 दिसंबर 2024 को की गई। यह पद 1 जून 2024 को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा के कार्यकाल समाप्त होने के बाद से रिक्त था। न्यायमूर्ति मिश्रा 2019 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन के बाद NHRC के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले पहले गैर-सीजेआई थे। न्यायमूर्ति रामासुब्रमणियन की नियुक्ति से पहले, अंतरिम नेतृत्व NHRC सदस्य विजया भारती सयानी ने संभाला। ([Click here to read article](#))
- भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (ASSOCHAM), जो भारत के सबसे पुराने शीर्ष व्यावसायिक मंडलों में से एक है (स्थापना 1920), ने मनीष सिंघल को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। सिंघल, जिनके पास 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है, दीपक सूद का स्थान लेंगे, जिन्होंने पांच वर्षों तक सेवा की और मंडल के संचालन में सुधार कर एक मजबूत वित्तीय नींव छोड़ी। सिंघल का करियर टाटा मोटर्स, आयशर (वोल्वो), और फिक्की जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में नेतृत्व भूमिकाओं तक फैला है, जहां वे उप महासचिव थे। ([Click here to read article](#))
- आईएएस अधिकारी भुवनेश कुमार, जो उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के अधिकारी हैं, ने 1 जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के सीईओ का पदभार संभाला। UIDAI, जो आधार का संचालन करता है, भारत की डिजिटल पहचान संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भुवनेश कुमार, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्यरत हैं, अमित अग्रवाल (1993 बैच, आईएएस) का स्थान ले रहे हैं। कुमार के नेतृत्व में, UIDAI भारत की शासन व्यवस्था और सेवा वितरण में अपने महत्वपूर्ण योगदान को बनाए रखने की दिशा में काम करेगा। ([Click here to read article](#))
- 1 जनवरी 2025 को, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना (IAF) की पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार संभाला। उन्होंने एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा का स्थान लिया, जिन्होंने 39 वर्षों की विशिष्ट सेवा के बाद सेवानिवृत्ति ली। ([Click here to read article](#))

Defence News

- भारतीय सेना ने चित्तौड़ के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण पेंगोंग त्सो, लद्दाख में किया। यह कदम भारत-चीन सीमा के पास रणनीतिक और सांस्कृतिक उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 26 दिसंबर, 2024 को फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स द्वारा स्थापित यह प्रतिमा महाराज शिवाजी की वीरता और दूरदर्शिता के प्रतीक के रूप में खड़ी है। ([Click here to read article](#))
- भारत की रक्षा निर्यात में अद्वितीय वृद्धि देखी गई है, जो पिछले दशक में केवल 2,000 करोड़ रुपये से बढ़कर अब रिकॉर्ड 21,000 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है। 29 दिसंबर 2024 को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मूह छावनी में स्थित आर्मी वॉर कॉलेज (AWC) के दौरे पर यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा कि 2029 तक रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपये तक पहुँच जाएगा। ([Click here to read article](#))

Awards and Recognitions

- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल करते हुए जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक के लिए 'ग्रेट प्लेस टू वर्क' के रूप में पुनः प्रमाणन प्राप्त किया है। यह प्रतिष्ठित पहचान ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टिट्यूट, इंडिया द्वारा दी गई है, और यह SAIL का दूसरा लगातार प्रमाणन है, जिसे पहले दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक के लिए यह पुरस्कार मिला था। यह प्रमाणन SAIL की सकारात्मक कार्य वातावरण बनाने, विश्वास को बढ़ावा देने और अपने कर्मचारियों को नवाचारी HR प्रथाओं के माध्यम से सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। ([Click here to read article](#))
- युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2024 के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों, कोचों, विश्वविद्यालयों और संस्थाओं को मान्यता दी गई है। इन पुरस्कारों का वितरण भारत के राष्ट्रपति द्वारा 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा। इन पुरस्कारों का उद्देश्य खेल के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए समर्पण, प्रदर्शन और प्रगति को प्रोत्साहित और मान्यता प्रदान करना है। ([Click here to read article](#))
- भारत सरकार ने 2024 के प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है, जो खेलों में असाधारण योगदान को सम्मानित करता है। ([Click here to read article](#))
- भारतीय सिनेमा की प्रख्यात निर्देशक और लेखिका साई परांजपे को अजंता-एल्लोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (AIFF) 2025 में पद्मपाणि लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। अपनी बेहतरीन जीवन की वास्तविकता को दर्शाने वाली फिल्मों जैसे स्पर्श, चश्मे बददूर, कथा, और साज़ के लिए मशहूर परांजपे को भारत के समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक प्रमुख हस्ती माना जाता है, जिसने 1970 और 1980 के दशकों में विशेष पहचान बनाई। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा और मराठी साहित्य में उनके व्यापक योगदान को मान्यता देता है। ([Click here to read article](#))

Summits and Conferences News

- भारत 5 से 9 फरवरी 2024 के बीच पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट (WAVES) की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 'मन की बात' रेडियो कार्यक्रम के दौरान इस वैश्विक आयोजन की घोषणा की। यह समिट भारत को विश्वस्तरीय कंटेंट निर्माण और रचनात्मक सहयोग का केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तर्ज पर आयोजित WAVES में मीडिया, मनोरंजन और रचनात्मक उद्योगों के वैश्विक नेताओं का स्वागत किया जाएगा। ([Click here to read article](#))

Sports News

- कोनेरु हम्पी ने 37 वर्ष की आयु में न्यूयॉर्क में अपना दूसरा महिला विश्व रैपिड शतरंज चैम्पियनशिप खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। उनका सफर, जो सेवानिवृत्ति पर विचार करने से लेकर विश्व खिताब फिर से जीतने तक का है, उनकी दृढ़ता और खेल के प्रति जुनून को दर्शाता है। हम्पी की कहानी केवल शतरंज में जीत की नहीं है, बल्कि मातृत्व, पारिवारिक सहयोग और एक चुनौतीपूर्ण पेशेवर शतरंज करियर के संतुलन की भी है। ([Click here to read article](#))

- जसप्रीत बुमराह ने एक अद्वितीय उपलब्धि हासिल की, जब उन्होंने मेलबर्न के एमसीजी में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट पूरे करने वाले सबसे तेज़ भारतीय गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड कायम किया। बुमराह की यह उपलब्धि केवल उनकी गति के लिए ही नहीं, बल्कि इसे महज 44 टेस्ट मैचों में प्राप्त करने की दक्षता के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो पहले भारतीय रिकॉर्ड को मोहम्मद शमी द्वारा स्थापित किया गया था। ([Click here to read article](#))
- केरल ने सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उन्होंने फाइनल में चंडीगढ़ को 34-31 के रोमांचक मुकाबले में हराया। यह पहली बार है जब केरल ने फाइनल में जगह बनाई और शानदार प्रदर्शन के साथ खिताब अपने नाम किया। टीम की सफलता सामूहिक प्रयास पर आधारित थी, जिसमें मुख्य खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। देवेन्द्र को 'चैंपियनशिप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी' और राहुल को 'सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर' के पुरस्कार से नवाजा गया। ([Click here to read article](#))
- 29 दिसंबर 2024 को हरियाणा स्टीलर्स ने प्रो कबड्डी लीग (PKL) खिताब जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। स्टीलर्स ने पुणे के श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए फाइनल में पटना पाइरेट्स को 32-23 से हराया। यह मुकाबला उनके खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन का गवाह बना, जिन्होंने इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैच में आक्रमण और रक्षा की रणनीतियों की परीक्षा हुई, जिसमें हरियाणा स्टीलर्स ने शुरुआत से ही नियंत्रण बनाए रखा और अपने रेडर्स और डिफेंडर्स के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर जीत दर्ज की। ([Click here to read article](#))

Schemes and Committees News

- 2 सितंबर 2024 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सात महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी, जिनकी कुल वित्तीय लागत ₹13,966 करोड़ है। ([Click here to read article](#))

Science and Technology News

- भारत की अंतरिक्ष यात्रा में बड़ी प्रगति हुई है, क्योंकि इसरो ने सफलतापूर्वक SpaDeX मिशन लॉन्च किया, जो अंतरिक्ष डॉकिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। 30 दिसंबर, 2024 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC SHAR) से PSLV-C60 रॉकेट द्वारा यह मिशन लॉन्च किया गया। इसने दो छोटे अंतरिक्ष यान, SDX01 (चेज़र) और SDX02 (टारगेट), को निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया। इस मिशन ने स्वायत्त डॉकिंग और अनडॉकिंग प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करते हुए इसरो को रूस, अमेरिका और चीन के बाद इस क्षेत्र में चौथा वैश्विक खिलाड़ी बना दिया। ([Click here to read article](#))

Important Days News

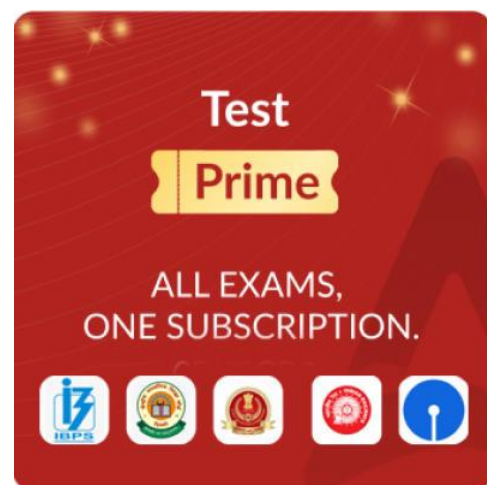
- नव वर्ष का दिन आनंद, आशा और नए प्रारंभ का समय है, जिसे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत

का प्रतीक है, जो वादों और संभावनाओं से भरा होता है। चमकदार आतिशबाजी से लेकर दिल से किए गए संकल्पों तक, लोग पिछले वर्ष पर विचार करने और खुले दिल से भविष्य का स्वागत करने के लिए एक साथ आते हैं। जैसे ही हम 2025 में प्रवेश कर रहे हैं, आइए इस विशेष दिन के इतिहास और उत्सवों का अन्वेषण करें। ([Click here to read article](#))

- ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को मनाया जाता है और यह नए साल की शुरुआत को शांति, एकता और परिवारों के प्रति सराहना के साथ जोड़ता है, जो हमारे जीवन में खुशी और स्थिरता लाते हैं। यह दिन विश्व शांति, समुदायों के बीच संबंधों और परिवारों को मजबूत करने के महत्व पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक शांति और समझ को बढ़ावा देना है, और संघर्षों को हल करने और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करना है। ([Click here to read article](#))

Obituaries News

- जिमी कार्टर, संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति, का उनके गृहनगर प्लेन्स, जॉर्जिया में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपने मजबूत नैतिक मूल्यों, मानवीय कार्यों और कैंप डेविड समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाने वाले कार्टर के राष्ट्रपति काल को आर्थिक मंदी और ईरान बंधक संकट जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक अवधि के राष्ट्रपति रहने के बावजूद, कार्टर ने अपने वैश्विक शांति प्रयासों के लिए सम्मान अर्जित किया और 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता। ([Click here to read article](#))
- प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक और पद्म श्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता कट्टुंगल सुब्रह्मण्यम मणिलाल, जिनकी आयु 86 वर्ष थी, 1 जनवरी 2025 को त्रिशूर में आयु संबंधित बीमारियों के कारण निधन हो गया। वह 17वीं सदी की लैटिन वनस्पति रचनाएँ "हॉर्टस मलबारिकस" का अंग्रेजी और मलयालम में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध थे, और भारत की समृद्ध वनस्पतिक धरोहर के दस्तावेजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ([Click here to read article](#))



Static Takeaways

Sr. No	Bank/Org/Country/State	Static Details
1	आरबीआई	राज्यपाल - संजय मल्होत्रा मुख्यालय - मुंबई
2	एसबीआई	एमडी - चल्ला श्रीनिवासु सेट्टी प्रधान कार्यालय- मुंबई
3	ईपीएफओ	केंद्रीय पीएफ आयुक्त - रमेश कृष्णमूर्ति मुख्यालय - नई दिल्ली
4	राष्ट्रीय सहकारी बैंक	एमडी - के.बी उप्रेती मुख्यालय - मुंबई
5	कॉसमॉस सहकारी बैंक	एमडी - श्रीमती अपेक्षिता थिप्से मुख्यालय - पुणे
6	सीआरपीएफ	महानिदेशक - अनीश दयाल सिंह
7	ब्राजील	राष्ट्रपति - लूला दा सिल्वा राजधानी - ब्राज़ीलिया
8	वियतनाम	राष्ट्रपति - लुओंग कुओंग राजधानी - हनोई
9	नेपाल	पीएम- केपी शर्मा ओली राजधानी - काठमांडू
10	चीन	राष्ट्रपति - शी जिनपिंग राजधानी - बीजिंग
11	स्विट्जरलैंड	राष्ट्रपति - वियोला एमहर्ड राजधानी - बर्न
12	केरल	राज्यपाल. अर्लेकर सीएम- पिनाराई विजयन राजधानी - तिरुवनंतपुरम
13	तमिलनाडु	राज्यपाल - आर.एन. रवि मुख्यमंत्री - एम.के. स्टालिन राजधानी - चेन्नई
14	हरियाणा	राज्यपाल - बंडारू दत्तात्रेय सीएम- नायब सिंह सैनी राजधानी - चंडीगढ़
15	छत्तीसगढ़	गवर्नर - रामेन डेका सीएम-विष्णुदेव साय राजधानी - रायपुर
16	जम्मू और कश्मीर	उपराज्यपाल-मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री - उमर अब्दुल्ला राजधानी - जम्मू
17	तेलंगाना	राज्यपाल - जिष्णु देव वर्मा सीएम - रेवंत रेड्डी राजधानी - हैदराबाद
18	गृह मंत्री	श्री. अमित शाह
19	रक्षा मंत्री	श्री. -राजनाथ सिंह